भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2886
बुधवार, 26 मार्च, 2025 (5 चैत्र, 1947, (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

2886 श्री नारायण कोरागप्पाः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पर एक प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है;
(ख) यदि हां, तो उन प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पीएसीएस) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहाँ यह प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई;
(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने और 500 पीएसीएस की आधारशिला रखी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) कर्नाटक राज्य में स्थापित किए जाने वाले पीएसीएस का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में नव स्थापित पीएसीएस का क्या प्रभाव है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): जी हाँ, मान्यवर। सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को 'सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' को पायलट परियोजना के रूप में शुरू करने की मंजूरी दी है । इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार (GoI) की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे कि कृषि अवसंरचना कोष ((AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), आदि के अभिसरण से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों, आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण करना शामिल है।

(ख): योजना की पायलट परियोजना के अंतर्गत, 11 राज्यों की 11 पैक्स में गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका राज्य-वार ब्योरा निम्नानुसार है:

क्रम.सं.	राज्य	जिला	पैक्स का नाम	गोदाम की क्षमता (मीट्रिक टन)
1.	महाराष्ट्र	अमरावती	नेरिपांगलाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था	3,000
2.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	बहुद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड, कोटवा पांडेय	1,500
3.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी मर्यादित, परसवाड़ा	500
4.	गुजरात	अहमदाबाद	चंद्रनगर ग्रुप सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड	750
5.	तमिलनाडु	थेनी	सिलामरथुपट्टी प्राथमिक कृषि ऋण समिति	1,000
6.	राजस्थान	श्री गंगानगर	घुमुडवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड	250
7.	तेलंगाना	करीमनगर	प्राथमिक कृषि ऋण समिति लिमिटेड, गंभीरोपेट	500
8.	कर्नाटक	बीदर	प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, एकंबा	1,000
9.	त्रिपुरा	गोमती	खिलपाड़ा प्राथमिक कृषि ऋण समिति लिमिटेड	250
10.	असम	कामरूप	2 नंबर पब बोंगशर जी.पी.एस.एस लिमिटेड	500
11.	उत्तराखंड	देहरादून	बहुद्देश्यीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, सहसपुर	500
	कुल			**9,750**

(ग): उपरोक्त के अतिरिक्त, पायलट परियोजना के तहत 500 अतिरिक्त पैक्स की आधारशिला रखी गई है। अभी तक, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 575 पैक्स को चिन्हित किया जा चुका है, जिनका राज्य-वार ब्योरा **संलग्नक** में संलग्न है ।

(घ): मंत्रालय देश भर की सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करने के लिए 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना और उन्हें सुदृढ़ करने की योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके लिए एक मार्गदर्शिका (मानक प्रचालन प्रक्रिया) का विमोचन भी किया जा चुका है । मार्गदर्शिका

के अनुसार, कर्नाटक राज्य में वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 218 पैक्स स्थापित करने के लक्ष्य की तुलना में 128 पैक्स का गठन किया जा चुका है ।
इसके अलावा, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की पायलट परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के बीदर जिले में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, एकंबा में 1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का भी निर्माण किया जा चुका है ।

(ङ): विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की पायलट परियोजना के परिणामस्वरूप पैक्स स्तर पर कुल 9,750 मीट्रिक टन विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता का सृजन किया जा चुका है । पैक्स स्तर पर गोदाम के निर्माण का उद्देश्य पर्याप्त विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता का सृजन करके खाद्यान्न की बर्बादी को कम करना, देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, फसलों की मजबूरन बिक्री को रोकना और किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाना है । चूंकि पैक्स खरीद केंद्र के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के रूप में भी काम कर सकते हैं, इसलिए खाद्यान्न को खरीद केंद्रों तक पहुंचाने और फिर से भांडागारों से एफपीएस तक स्टॉक को वापस लाने में होने वाली लागत को भी बचाया जा सकता है।

*****

संलग्नक

चिन्हित पैक्स/ लैम्पस का राज्य-वार ब्योरा

क्रम.सं.	राज्य का नाम	चिन्हित पैक्स/LAMPS
1.	महाराष्ट्र	258
2.	गुजरात	47
3.	त्रिपुरा	8
4.	हरियाणा	11
5.	ओडिशा	78
6.	उत्तर प्रदेश	24
7.	जम्मू और कश्मीर	11
8.	राजस्थान	100
9.	मध्य प्रदेश	38
कुल		**575**

*****